साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 6, अंक : 47 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 14 जुलाई से 20 जुलाई 2021 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

हर मिनट भूख के कारण दम तोड़ रहे हैं 11 लोग, कोविड-19, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन है बड़ी वजह

मुंबई। हर मिनट भूख के कारण औसतन 11 लोग दम तोड़ रहे हैं। जिसके लिए काफी हद तक कोविड-19, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार है। यह जानकारी हाल ही में ऑक्सफेम द्वारा जारी नई रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज में सामने आई है7 अनुमान है कि दुनिया भर में करीब 15.5 करोड़ लोग गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं, जोकि पिछले साल की तुलना में 2 करोड़ ज्यादा है।

दुख की बात यह है कि इनमें से दो-तिहाई सिर्फ इसलिए भुखमरी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके देश सैन्य संघर्ष में लगे हुए हैं। हालांकि देखा जाए तो हम में से बहुत से लोगों के लिए यह महज यह कुछ आंकड़ें हैं पर इनका वो दर्द वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने इस स्थिति का सामना किया है। जब से यह महामारी शुरू हुई है, तब से अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की संख्या में छह गुना इजाफा हुआ है, जो बढ़कर 5.2 लाख से ज्यादा हो गई है। महामारी शुरु होने के बाद से संघर्ष, भुखमरी के लिए जिम्मेवार सबसे बड़ा कारण है। यदि 23 संघर्ष-ग्रस्त देशों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उनमें करीब 10 करोड़ लोग इसके चलते खाद्य संकट का सामना करने को मजबूर हैं। वहीं विडंबना देखिए वैश्विक स्तर पर पिछले साल सेना पर किए खर्च में करीब 2.7 फीसदी का इजाफा किया गया है, जो करीब 3.8 लाख करोड़ के बराबर है7 यह रकम इतनी है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा भुखमरी को रोकने के लिए आवश्यक जरूरतों को छह बार से ज्यादा पूरा कर सकती है। वहीं जून के मध्य तक के आंकड़ों को देखें तो इथियोपिया, मेडागास्कर, दक्षिण सूडान और यमन में भीषण अकाल की स्थिति का सामना करने वाले लोगों की संख्या 521,814 थी जोकि पिछले वर्ष कि तुलना में करीब 500 फीसदी ज्यादा है। गौरतलब है कि पिछले साल यह संख्या 84,500 दर्ज की गई थी। अनुमान है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 2021 के अंत तक 74.5 करोड़ पर पहुंच जाएगी, जोकि महामारी के पहले की तुलना में करीब 10 करोड़ ज्यादा है। एक तरफ महामारी के दौरान जहां अमीर और अमीर होते गए। अनुमान है कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति में पिछले वर्ष 30.7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जोकि 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय अपील को 11 बार पूरा करने के लिए काफी है। अनुमान है कि महामारी की शुरुवात से वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में में 3.5 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि गरीबी में 16 फीसदी की वृद्धि हुई है।

भारत की भी कोई अच्छी नहीं है स्थिति- वहीं यदि भारत की बात करें तो वहां लाखों लोग भोजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में भारत को एक हंगर हॉटस्पॉट के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यदि 2020 के आंकड़ों को देखें तो भारत में करीब 19 करोड़ लोगो कुपोषण का शिकार हैं। वहीं पांच वर्ष से कम उम्र के करीब एक तिहाई बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। जहां इस वायरस की चपेट में आने के बाद भारत में लोगों की दाल जैसी आवश्यक खाद्य पदार्थों की खपत में 64 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं हरी सब्जियों की खपत में 73 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। देश में 70 फीसदी से अधिक लोगों ने माना है कि महामारी के पहले की तुलना में उनके भोजन की मात्रा में कमी आई है। इसके लिए काफी हद तक आय में आई कमी जिम्मेवार है। देश में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन न होना भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेवार हैं। वहीं स्कूलों के बंद होने का भी कहीं न कहीं हाथ है। देश के 15 राज्यों में 47,000 परिवारों पर किए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि बड़े पैमाने पर नौकरी छूटने के कारण खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में परिवार ने अपनी आय का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा खो दिया है। अकेले अप्रैल 2021 में करीब 80 लाख लोगों की नौकरियां छिन गई थी। यही नहीं रिपोर्ट का मानना है कि देश की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली उन लोगों तक मदद पहुंचाने में विफल रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। सरकार अभी भी अपनी सार्वजनिक वितरण योजना के लिए 2011 की जनगणना से जुड़े आंकड़ों पर निर्भर करती है, जिसके चलते करीब 10 करोड़ लोग जो राशन प्राप्त करने के हकदार थे, उन्हें यह मदद नहीं मिल पाई थी। अनुमान है कि इस योजना के लिए हकदार केवल 57 फीसदी आबादी को ही इसका लाभ मिल पा रहा है। यही नहीं देश में भुखमरी के लिए स्कूलों के बंद होने को भी एक कारण माना गया है। देश में करीबी 12 करोड़ बच्चे स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे मील पर निर्भर थे, स्कूल और कई भोजन कार्यक्रमों के बंद होने के कारण बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाया था।

पूरी तरह टीकाकरण करने के लिए करना होगा 57 वर्षों का इन्तजार- रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि और महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट का नतीजा है कि वैश्विक खाद्य कीमतों में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कीमतों में आए इस उछाल ने भी लाखों लोगों को भी भुखमरी के दलदल में धकेलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि आज वैक्सीन के मामले में दुनिया में जो असमानता है उससे लगभग 684.8 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं भारत जैसे उभरते हुए हंगरस्पॉट के लिए यह नुकसान उसकी जीडीपी के 27 फीसदी से अधिक का हो सकता है। ऑक्सफैम की गणना के अनुसार वर्तमान में जिस दर से टीकाकरण किया जा रहा है यदि वैसा ही चलता रहा तो कम आय वाले देशों को अपनी पूरी आबादी का कोविड टीकाकरण करने के लिए करीब 57 साल का इन्तजार करना होगा। ऐसे में करीब नौकरी और आय के स्रोतों के खत्म होने और बीमारी के कारण खराब स्वास्थ्य के चलते और करीब 13.2 करोड़ लोग कुपोषित हो जाएंगें।

साभार - डाउन टू अर्थ

अभी भी खुले में शौच करते हैं दुनिया के 49.4 करोड़ लोग

नोएडा। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले पांच वर्षों में 2015 से 2020 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। पर इसके बावजूद अभी भी दुनिया भर में करीब 49.4 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं, जिसमें भारत की भी करीब 15 फीसदी आबादी शामिल है। यदि देखा जाए तो दुनिया के 55 देशों में अभी भी 5 फीसदी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करती है। जहां उप सहारा अफ्रीका में स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है।

हालांकि देखा जाए तो 2015 से 2020 के बीच खुले में शौच करने वालों की संख्या में करीब 24.5 करोड़ की गिरावट आई है। जो काफी हद तक मध्य और दक्षिण एशिया की वजह से संभव हो पाया है। जहां पिछले पांच वर्षों में खुले में शौच करने वालों की संख्या में 19.6 करोड़ की कमी आई है, इसमें एक बड़ी आबादी भारत की भी है। यही नहीं जहां पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसकी संख्या में 2.4 करोड़ की कमी आई है वहीं दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन में यह कमी करीब एक करोड़ दर्ज की गई है। देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश क्षेत्र 2030 तक खुले में शौच करने की कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने की राह पर हैं। इस मामले में उप-सहारा अफ्रीका बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जबकि ओशिनिया में खुले में शौच की दर में वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी हाल ही में डब्लूएचओ और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से जारी रिपोर्ट %प्रोग्रेस ऑन हाउसहोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन 2000-2020नामक रिपोर्ट में सामने आई है। अफ्रीका में दक्षिण सूडान, चाड और नाइजर ऐसे देश हैं जहां अभी भी 60 फीसदी से ज्यादा आबादी खुले में शौच करती है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, गाम्बिया, मायोट, रीयूनियन, सैंटो हेलेना, सेशेल्स जैसे देश हैं जहां कि एक फीसदी से भी कम आबादी खुले में शौच करती है। यदि भारत से जुड़े आंकड़ों को देखें तो जहां 2015 में देश की करीब 29 आबादी खुले में शौच करने जाती थी, वो 2020 में घटकर 15 फीसदी रह गई है। जो स्पष्ट तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की कहानी कहता है। इस लिहाज से भारत इस दिशा में हर साल करीब 2.96 फीसदी की दर से प्रगति कर रहा है। वहीं यदि ग्रामीण भारत की बात करें तो 2015 में देश की करीब 40 फीसदी ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती थी, लेकिन 2020 में यह आंकड़ा घटकर 22 फीसदी रह गया है। इसी तरह शहरी भारत में जहां 7 फीसदी आबादी 2015 के दौरान खुले में शौच करती थी वो 2020 में घटकर एक फीसदी से भी कम रह गई है। देखा जाए तो दुनिया भर में 2015 से 2020 के बीच इस दिशा में जो प्रगति हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का ही है। जहां पिछले पांच वर्षों में इसमें 14 फीसदी की गिरावट आई है।

लागत - ग्राउन्ड टू अर्थ

मानसून की बेरुखी, मध्य प्रदेश के 21 जिले बारिश को तरसे

भोपाल । जुलाई का पहला पखवाड़ा बीतने को है, लेकिन मध्यप्रदेश में अभी तक अपेक्षित बरसात नहीं हुई है। मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालात यह है कि मंगलवार सुबह तक प्रदेश के 21 जिलों में बारिश सामान्य से काफी कम तक बरसात हुई है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी तीन-चार दिन तक तेज बौछारें पड़ने की संभावना नहीं है। इस दौरान राजधानी सहित सभी जिलों में अधिकतम तापमान बढ़ने लगेगा। उधर मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक इंदौर में 1.2, श्यौपुरकला में एक, धार में 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्रीसेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से तीन डिग्रीसे. अधिक रहा। साथ ही सोमवार के अधिकतम तापमान (33.3 डिग्रीसे.) की तुलना में 1.2 डिग्रीसे. अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्रीसे. रिकार्ड किया गया। जो सामान्य से एक डिग्रीसे. अधिक रहा। यह सोमवार के न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्रीसे. के मुकाबले 0.5 डिग्रीसे. अधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़कर ऊपरी हवा के चक्रवात में परिवर्तित हो गया है। उधर गुजरात पर बना कम दबाव का क्षेत्र सौराष्ट्र की तरफ खिसक गया है। इन दोनों सिस्टम के बीच से एक ट्रफ गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहा है। पूर्वी-पश्चिमी ट्रफ विदर्भ से होकर गुजर रहा है। चार वेदर सिस्टम मौजूद रहने के बाद भी मप्र को नमी नहीं मिल रही है। इससे बौछारें पड़ने का सिलसिला थमा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में हवा का रुख पूर्वी हो गया है। इस वजह से नमी आने का सिलसिला थमा है। तीन दिन बाद हवा का रुख बदलकर फिर पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में कहीं-कहीं फिर गरज-चमक के साथ बरसात का दौर शुरू होने की संभावना है। मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे मप्र में सीजन की अभी तक 208 मिमी. बारिश हुई है। जो सामान्य (240 मिमी.) की तुलना में 13 फीसद कम है। इसके अलावा प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, धार, आलीराजपुर, आगर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्यौपुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, कटनी, जबलपुर, बालाघाट में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है।

मध्य प्रदेश को मिलेगी अब तक की सबसे सस्ती सोलर बिजली, दो साल में शुरू होगा उत्पादन

भोपाल । नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा सोमवार को आगर के 550 मेगावॉट सोलर पावर प्लांट की दो यूनिट के लिए रिवर्स बिड (निविदा) 2.73 रुपये प्रति यूनिट के बेस टैरिफ से मंजूर कर ली गई। बिड ऑफर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की 12 कंपनियों ने हिस्सा लिया। न्यूनतम ऑफर के आधार पर क्रमशः दोनों यूनिट के लिए बीमपाव एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड और अवाडा एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड का चयन किया गया। बीमपाव एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड से 2.444 रुपये प्रति यूनिट और अवाडा एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड की ओर से 2.459 प्रति रुपये यूनिट न्यूनतम ऑफर प्राप्त हुआ। मध्य प्र देश के लिए अब तक की यह सबसे सस्ती सोलर बिजली होगी।

उल्लेखनीय है कि विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक रीवा सौर परियोजना को तत्कालीन न्यूनतम सोलर टैरिफ 2.97 रुपये प्राप्त हुआ था। यह परियोजना तीन जनवरी 2020 से पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कर रही है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष एसपीएस परिहार, प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा संजय दुबे और प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम दीपक सक्सेना और आयोग के सचिव शैलेंद्र सक्सेना की उपस्थिति में प्रक्रिया पूर्ण की गई। आगर में निजी निवेश से लगभग 1950 करोड़ रुपये की लागत से एक हजार हेक्टेयर भूमि पर 550 मेगावाट की दो यूनिट स्थापित की जाएंगी। परियोजना से मार्च 2023 में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परियोजना स्थापना के दौरान लगभग 5500 और संचालन में लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। विभाग ने सौर परियोजना से 26 जनवरी 2020 को निविदा आमंत्रित की थी। निविदा की अंतिम तारीख 21 जून 2021 तक तीन अंतरराष्ट्रीय, नौ राष्ट्रीय और तीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया। इनमें से न्यूनतम टैरिफ के आधार पर चुनी गई 12 कंपनियों टाटा पावर, रिन्यू पावर, बीमपाव एनर्जी, एनटीपीसी, अयान, रिन्यूएबल पावर, टोरेंट पावर, एसजेवीएन लिमिटेड, अज्यूर पावर, अल्जोमेह एनर्जी, एक्मे सोलर, स्प्रिंग ग्रीन और अवाडा एनर्जी ने रिवर्स ऑक्शन (नीलामी) में भाग लिया। दीपक सक्सेना ने बताया कि शाजापुर सौर पार्क में भी 15 विकासकों द्वारा बिड प्रक्रिया में सहभागिता की गई है। इसकी पुनः नीलामी 19 जुलाई को किया जाना है। नीमच सौर पार्क के लिए 15 जुलाई तक प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। रम्स (रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड) द्वारा प्रदेश में आगर 550 मेगावॉट, शाजापुर 450 मेगावाट और नीमच 500 मेगावॉट सौर परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है।

सृष्टि का भविष्य संकटग्रस्त

प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच भावनात्मक संबंध था। मानव अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रकृति के उपहारों को ग्रहण करता था। प्रकृति के किसी भी अवयव को क्षति पहुँचाना पाप समझा जाता था। बढ़ती जनसंख्या एवं भौतिक विकास के फलस्वरूप प्रकृति का असीमित दोहन प्रारम्भ हुआ। भूमि से हमने अपार खनिज सम्पदा, डीजल, पेट्रोल आदि निकाल कर धरती की कोख को उजाड़ दिया। वृक्षों को काट-काट कर मानव समाज ने धरती को नग्न कर दिया। वन्य जीवों के प्राकृतवास वनों के कटने के कारण वन्य-जीव बेघर होते गए। असीमित औद्योगीकरण के कारण लगातार जहर उगलती चिमनियों ने वायुमण्डल को विषाक्त एवं निष्प्राण बना दिया। हमारी पावन नदियाँ अब गंदे नाले का रूप ले चुकी हैं। नदियों का जल विशाक्त होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियाँ एवं अन्य जलीय जीव तड़प-तड़प कर मर रहे हैं। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से कानों के परदों पर लगातार घातक प्रभाव पड़ रहा है। लगातार घातक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भूमि को उसरीला बनाता जा रहा है। पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है तथा लगातार तापक्रम बढ़ने से पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है जिससे पृथ्वी का अस्तित्व संकटग्रस्त होता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आज विभिन्न घातक स्वरूपों में विद्यमान है जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सृष्टि का भविष्य संकटग्रस्त है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख स्वरूप निम्न प्रकार हैं-

1. वायु प्रदूषण- मानव को प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार मिला है और वह है- वायु। यह उपहार सभी जीवों का आधार है। मानव बिना भोजन एवं बिना जल के कुछ समय भले ही व्यतीत कर ले, बिना वायु के वह दस मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। यह अत्यंत चिन्ता का विषय है कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायिनी वायु लगातार जहरीली होती जा रही है। शहरों का असीमित विस्तार, बढ़ता औद्योगीकरण, परिवहन के साधनों में लगातार वृद्धि तथा विलासिता की वस्तुएं (जैसे- एयरकन्डीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि) वायु प्रदूषण को लगातार बढ़ावा दे रही हैं। मानव 24 घण्टे में लगभग 22,000 बार साँस लेता है तथा इसमें प्रयुक्त वायु की मात्रा लगभग 35 गैलन या 16 किग्रा है। ऐसी वायु जो हानिकारक अवयवों से मुक्त हो, उसे शुद्ध वायु कहते हैं। वायु के मुख्य संघटकों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइ ऑक्साइड हैं। उक्त के अतिरिक्त वायुमण्डल में थोड़ी मात्रा में आर्गन या नियॉन जैसी विरल गैसें भी पाई जाती हैं। आधुनिक युग में उद्योगों की चिमनियों, बढ़ते वाहनों एवं अन्य कारणों से वायुमण्डल में अनेक हानिकारक गैसें मिश्रित हो रही हैं जिनमें सल्फर डाइ ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन एवं फार्मेलिडहाइड मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त सड़कों पर चल रहे वाहनों से निकला सीसा (लेड), अधजले हाइड्रोकार्बन और विषैला धुआँ भी वायुमण्डल को लगातार प्रदूषित कर रहे हैं। वायुमण्डलीय वातावरण के इस असंतुलन को 'वायु प्रदूषण' कहते हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण आसमान अब भूरा दिखाई देता है। विषाक्त वायु को अवशोषित करने वाले वृक्षों के कटान से वायुमण्डल में प्राणवायु ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है तथा दूषित गैसों का दबाव बढ़ रहा है। विभिन्न वायु प्रदूषक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं। वायुमण्डल में इन विषाक्त गैसों की उपस्थिति के कारण स्मॉग (स्मोक + फॉग) का निर्माण होता है। लंदन एवं लॉस एंजेल्स में स्मॉग निर्माण से अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसो सायनाइड गैस से वायु इतनी प्रदूषित हुई जिससे हजारों लोग मौत एवं विकलांगता का शिकार हो गए। प्रदूषित वायु मानव के श्वसन-तंत्र को कुप्रभावित करती है। क्त के अतिरिक्त प्रदूषित वायुमण्डल के कारण धातु की बनी वस्तुओं में अनेक बार रंगाई करनी पड़ती है। वायु प्रदूषण से ऐतिहासिक धरोहरों को भी क्षति पहुँचती है। ताजमहल का ''पत्थर कैंसर'' वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। धुआँ तथा धूल के सूक्ष्म कणों के कारण सूर्य का प्रकाश भूमि तक ठीक से नहीं पहुँच पाता जिससे आकाश की निर्मलता घटती है। इससे वायुयानों के चालन में कठिनाई होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वायु प्रदूषण से होने वाले असंतुलन का परिणाम हमें चातुर्दिक दिखाई दे रहा है। इस समस्या के समाधान के लिये भारत सरकार ने इस दिशा में वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम- 1981 पारित किया। केंद्र में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की गई। जिन उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में यथोचित कार्यवाही नहीं की जाती उनके विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

वायु प्रदूषण को रोकने हेतु प्रमुख उपाय निम्न प्रकार हैं- 1. वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधे वायुमण्डलीय कार्बन डाइ ऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अतः सड़कों, नहर पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भू-भाग पर व्यापक रूप से वृक्ष लगाए जाने चाहिए ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ वायुमण्डल भी शुद्ध हो सके। औद्योगिक क्षेत्रों के निकट हरि पट्टियाँ विकसित की जानी चाहिए जिसमें ऐसे वृक्ष लगाए जायें जो चिमनियों के धुएँ से आसानी से नष्ट न हों तथा घातक गैसों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हों। पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है।

2. औद्योगिक इकाइयों को प्रयास करना चाहिए कि वायुमण्डल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखें जिसके लिये प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाएं।

3. उद्योगों में चिमनियों की ऊँचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आस-पास कम से कम प्रदूषण हो।

4. पेट्रोल कारों में कैटेलिटिक कनवर्टर लगाने से वायु प्रदूषण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार की कारों में सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग किया जाना चाहिये।

5. घरों में धुआँ रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिये।

6. जीवाश्म ईंधनों (पेट्रोलियम, कोयला), जो वायुमण्डल को प्रदूषित करते हैं, का प्रयोग कुछ कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

हमारा वायुमण्डल हमारे स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है, इस तथ्य के विपरीत हमने विभिन्न पर्यावरणीय तंत्रों को इस सीमा तक परिवर्तित कर दिया है जिसका परोक्ष दुष्परिणाम हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इस स्थिति पर ध्यान न देना आत्महत्या सिद्ध होगा। अतः हम सबको मिलकर इस धरती पर प्रलयकारी परिस्थिति पैदा होने की आशंका को टालने के लिये निरंतर संघर्ष करना होगा। वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्याओं को हम भले ही रोक तो नहीं सकते, परंतु कुछ विशिष्ट सुरक्षा उपायों से कुछ हद तक पर्यावरण संरक्षण, संतुलन व विकास में योगदान कर सकते हैं।

साभार - डाउन टू अर्थ

वैश्विक ताप वृद्धि

सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी का ताप इससे टकराने वाले सूर्य विकिरणों तथा अंतरिक्ष में वापस लौट जाने वाली किरणों द्वारा नियंत्रित होता है। जब वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो इस गैस की मोटी परत किरणों को परावर्तित होने से रोकती है। यह मोटी ग्रीन हाउस की काँच की दीवार तथा कार की खिड़की के काँच की भाँति होती है। यह दोनों ही गर्मी को बाहर विकिरित होने से रोकती है। इसे 'ग्रीन हाउस प्रभाव' कहते हैं। यही क्रिया प्रकृति में भी होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें एक मोटी परत पृथ्वी के वातावरण में बना लेती हैं जो गलास हाउस के काँच की भाँति ही कार्य करती है अर्थात सूर्य उष्मा जो भीतर आती है पूरी की पूरी वापस नहीं जाने पाती जिससे विश्व स्तर पर वातावरण की निचली परत में वायु का ताप बढ़ जाता है। बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को समुद्रों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है परंतु औद्योगीकरण तथा ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से समुद्री अवशोषण क्षमता की तुलना में वायु मण्डल में अधिक कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। इस प्रकार वायुमण्डल में कार्बन डाइ ऑक्साइड की सांद्रता निरंतर बढ़ रही है। कार्बन डाइ ऑक्साइड पृथ्वी के ताप में 50 प्रतिशत एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि करती है। कुछ अन्य गैसें जैसे सल्फर डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 2050 में पृथ्वी का ताप 1 से 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से ध्रुवों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, साइबेरिया एवं अलास्का इससे सर्वाधिक प्रभावित होंगे। ध्रुवीय बर्फ पिघल जायेगी। 5 डिग्री ताप वृद्धि से समुद्र स्तर में 5 मीटर की वृद्धि होगी जो सेनफ्रांसिस्को एवं शंघाई जैसे उच्च जनसंख्या वाले तटीय शहरों पर प्रभाव डालेगा।

दुनिया में 80 करोड़ से अधिक आबादी भुखमरी की शिकार, एशिया की हालत सबसे खराब

नई दिल्ली। दुनियाभर में भुखमरी का गंभीर संकट मंडरा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान कोविड-19 महामारी का है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की ताजा रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021÷ में अनुमान लगाया गया है कि दुनियाभर में 81.1 करोड़ लोग 2020 में भुखमरी से जूझ रहे थे। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया का हर दसवां शख्स भूखा है। एफएओ के अनुसार, ये आंकड़े बताते हैं कि अगर 2030 तक दुनिया से भुखमरी का खत्म करना है तो व्यापक प्रयास करने होंगे।

एफएओ की इस रिपोर्ट में महामारी के दौर में पहली बार भुखमरी का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट एफएओ, इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट (आईएफएडी), यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड (यूनिसेफ), यून वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से 12 जुलाई को जारी की है। यूएन की इन पांचों एजेंसियों के प्रमुख ने संयुक्त रूप से लिखी गई प्रस्तावना में कहा है, पिछले साल की यह रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी असर डाला है जिससे दुनिया अप्रत्याशित मंदी की ओर बढ़ रही है। ऐसी मंदी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा और बच्चों सहित लाखों लोगों की पोषण सुरक्षा खतरे में है। अगर हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी।÷ वह आगे लिखते हैं कि दुर्भाग्य से महामारी ने हमारे खाद्य तंत्र की कमजोरी उजागर कर दी है जिसने दुनियाभर में लोगों की जिंदगी और उनकी आजीविका को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 72 से 81.1 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार थे जो 2019 के मुकाबले 16 करोड़ अधिक है। 2020 में 2.37 बिलियन लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। दुनिया का कोई भी हिस्सा भुखमरी से अछूता नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण भोजन की महंगाई, गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण दुनियाभर में 3 बिलियन लोग गुणवत्तापूर्ण भोजन से वंचित हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ्रीका और एशिया में पांच साल के बच्चों में कुपोषण की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 सालों में जलवायु की आपदाएं और आर्थिक मंदी बढ़ी है। महामारी ने इनके असर को और बढ़ा दिया है जिसके फलस्वरूप निम्न और मध्य आय वाले देशों में भुखमरी बढ़ रही है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2020 में लगाए गए लॉकडाउन जैसे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण दुनियाभर में भुखमरी पिछले दशकों के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, भुखमरी की शिकार दुनिया की आधी से अधिक एशिया में रहती है। एशिया में 41.8 करोड़ लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं। जबकि अफ्रीका में 28.2 करोड़ लोग ऐसे हालात में गुजर-बसर कर रहे हैं। अफ्रीका में 21 प्रतिशत आबादी भुखमरी की शिकार है। 2019 की तुलना में अफ्रीका में भूखे लोगों की संख्या 4.6 करोड़ बढ़ी है, वहीं एशिया में ऐसे लोगों की संख्या में 5.7 करोड़ का इजाफा हुआ है। लैटिन अमेरिका में 1.4 करोड़ भुखमरी के शिकार बढ़े हैं। कुपोषण से ग्रस्त अधिकांश बच्चे अफ्रीका और एशिया में ही हैं।

साभार - डाउन टू अर्थ

मौसम और जलवायु से जुड़ी सटीक जानकारी हर साल बचा सकती है 23,000 लोगों की जान

नई दिल्ली। मौसम पूर्वानुमान, जलवायु से जुड़ी सटीक जानकारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करके हर वर्ष करीब 23,000 लोगों की जान बचाई जा सकती है, यही नहीं इससे करीब 12 लाख करोड़ रुपए (16,200 करोड़ डॉलर) का लाभ भी होगा। साथ ही यह सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करने में मददगार होंगी। यह जानकारी 8 जुलाई 2021 को एलायंस फॉर हाइड्रोमेट डेवलपमेंट द्वारा जारी हाइड्रोमेट गैप रिपोर्ट में सामने आई है।

गौरतलब है कि मौसम पूर्वानुमान, जलवायु से जुड़ी सटीक जानकारी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को हाइड्रोमेट के रूप में जाना जाता है। यह प्रणालियां अपनी लागत से कम से कम दस गुना लाभ पैदा करती हैं और मौसम की चरम घटनाओं का मुकाबला करने में मददगार हो सकती हैं। इन सबके बावजूद अभी भी दुनिया के केवल 40 फीसदी देशों में मौसम और जल से जुड़े खतरों की प्रभावी पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणाली मौजूद है। यही नहीं पिछड़े और छोटे विकासशील द्वीपीय देशों में इनके लिए जरुरी आंकड़ों में भी अभी काफी कमी है। डब्ल्यूएमओ महासचिव पेटेरी तालास ने बताया कि हमारी जलवायु तेजी से बदल रही है। जहां पिछला दशक अब तक का सबसे गर्म दशक था। वहीं यदि औद्योगिक काल से पहले की तुलना में वैश्विक औसत तापमान को देखें तो वो लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बावजूद हम जलवायु परिवर्तन के सबसे बदतर प्रभावों को रोकने के अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। हम वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पेरिस समझौते के अनुरूप तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने से अभी भी काफी दूर हैं। यह सही है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना जरुरी है। साथ ही जलवायु और मौसम से जुड़े खतरों से निपटना और उनके लिए तैयार रहना भी अत्यंत जरुरी है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2021 में जलवायु अनुकूलन और खतरों से निपटने के लिए वित्त में बढ़ोतरी की है। जिससे सभी लोगों, विशेष रूप से जो सबसे कमजोर तबके से सम्बन्ध रखते हैं वो इस तरह की मौसम और जलवायु सम्बन्धी घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार हो सकें। वहीं प्रोफेसर तालास का कहना है कि विज्ञान और आंकड़ों पर आधारित मौसम और जलवायु सेवाएं प्रभावी जलवायु अनुकूलन की नींव हैं। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैड्रिड में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-25) में एलायंस फॉर हाइड्रोमेट डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया था। जिसका मकसद सभी के लिए मौसम, जलवायु, जल और सम्बंधित पर्यावरणीय सेवाओं को सुनिश्चित करना है, जिससे शाश्वत विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। अनुमान है कि मौसम पूर्वानुमान की मदद से उन क्षेत्रों को जो मौसम के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं, के आर्थिक उत्पादन में 716,250 करोड़ रुपए का वार्षिक लाभ हो सकता है। ग्लोबल कमीशन ऑन अडॉप्टेशन के अनुसार 2020 से 2030 के बीच जलवायु अनुकूलन पर किया गया 134.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश 522.3 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ देगा, जिनका मुख्य आधार हाइड्रोमेट सेवाएं हैं। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूनेप) के कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने कहा कि ÷यह महत्वपूर्ण है कि हम स्थानीय और वैश्विक स्तर पर जलवायु से जुड़े खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें और जलवायु अनुकूलन की की क्षमता को मजबूत करें। इस सफलता का एक बड़ा हिस्सा पूर्वानुमान और बचाव की क्षमता पर निर्भर करेगा। इसके लिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान, सही समय पर चेतावनी और जलवायु संबंधी सटीक जानकारी आवश्यक है।÷

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008